गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता

5623. **प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री 9 दिसम्बर, 1994 और 23 दिसम्बर, 1994 को क्रमशः राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं॰ 488 और तारांकित प्रश्न सं॰ 254 के दिये गये उत्तरों को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, महिलाओं सहित किसानों, फार्म कार्मिकों को नयी-विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता प्राप्त बीजों के उत्पादन पर प्रदर्शन, उन्नत यंत्रों के वितरण आदि के बारे में प्रशिक्षण पर सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुछ ही राज्यों पर निर्भरता

5624. **प्रो॰ राम बख्शसिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश को खाद्यान्नों की अपनी कुल आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ ही राज्यों पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अनाज उत्पादक राज्यों ने भी नकदी फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में धान की खेती वाले क्षेत्र में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जिन राज्यों के पास खाद्यान्नों के उत्पादन में मण्डी योग्य अधिक बचत है, वे अधिप्राप्ति के केन्द्रीय हिस्से में मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं। तथापि, सभी राज्य कुछ सीमा तक खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं।

(ख) अधिकतर राज्यों में खाद्यान्नों के साथ नकदी फसलें पैदा करने की सामान्य प्रथा है। खाद्यान्न उगाने वाले क्षेत्र को नकदी फसलों के क्षेत्र के अंतर्गत लाने का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है सिवाय इसके कि मोटे अनाजों वालों कुछ क्षेत्र पर तिलहन फसलों की खेती की जा रही है।

(ग) देश में धान की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ने 1980-81 से 1993-94 की अवधि के दौरान 0.49 प्रतिशत प्रतिवर्ष की मिश्रित विकास दर को दर्शाया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1993-94 के दौरान क्षेत्र में मामूली घटाव-बढ़ाव रहा है, जिसका श्रेय 1991-92 और 1992-93 के दौरान कुछ मुख्य धान पैदा करने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों में वर्षा की कमी को जाता है।

(घ) विभिन्न राज्यों में चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों (आई॰सी॰डी॰पी॰—चावल) में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

बीजों की आपूर्ति

5625. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीजों की आपूर्ति के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को कोई महत्व नहीं दिया गया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Schemes for Fishing in the Reservoir

5626. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh have submitted certain schemes regarding fishing in the reservoir for approval;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken by the Central Government to accord approval to these schemes; and

(d) by when these schemes are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Government of Madhya Pradesh had submitted a proposal for development of reservoir fisheries in the State with foreign assistance. The proposal included establishment of hatchery, rearing pond, fish seed farm, landing centres, communication systems, mechanised boats and fishermen's houses.

(c) and (d) The proposal of the State Government of Madhya Pradesh was posed for assistance to the European Economic Commission and they have informed that they are not in a position to consider the funding of the proposal. The State Government has been informed of the decision.

Technological Advancements/Improvisations made on bullock carts

5627. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are keeping a track on the technological advancements/ improvisations made on bullock carts that has been the traditional backbone of rural economy;

(b) whether it is a fact that there are 13 million animal driven vehicles (ADVs) in the country contributing about 35,000 megawatts of energy to the national economy every year and saving a substantial sum on imports of petroleum products to keep the tractors working; and

(c) whether Government are extending loans to farmers to buy tractors upto Rs. 30,000/- whereas there is no assistance to farmers to buy improvised versions of bullock carts, costing around Rs. 8,000/- only?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) As per Indian Lovestock Census 1987, there are 1,43,50,400 Animal Carts in India out of which 1,40,85,700 are in rural areas and 2,62,700 in urban areas. Assuming one loaded animal cart re quires 0.75 KW of power for its opera tion, the total animal power used in such operation (on limited studies) is about 10,760 MW. Further, assuming that aver age yearly animal cart use in rural area is 700 hours, the energy used per year is estimated as 7.53 x 106 MW hr. (28 Pcta Joules).

Animal drawn vehicles and tractors are relevant and complementary in Indian Agricultural Sector.

(c) During the financial year 1992-93 and 1993-94, a scheme was sanctioned for providing subsidy to fanners and group of farmers having perennially irrigated land holding between 6—8 acres or equivalent for purchase of tractors of power below 18 PTO H.P.

Loan for farm mechanisation is provided by the commercial and cooperative banks. Assistance is given under TRDP for purchase of bullock cart for families of small farmer, marginal farmer as well as agricultural and non-agricultural labourers living below poverty line in rural areas. The assistance is in the form of subsidy by the Government and term-credit by the financial Institutions. The ceiling on subsidy is fixed at Rs. 4000/-to Rs. 6000/- per family depending on the category of beneficiary. There is no ceiling limit on bank credit.

घोड़े की नस्लें

5628. श्री शिव प्रसाद जनपुरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कि.न-किस नस्ल के घोडे उपलब्ध हैं: